



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 1, 2017/कार्तिक 10, 1939

No. 421]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2017/KARTIKA 10, 1939

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 25 अक्टूबर, 2017

**संख्या टीएएमपी/14/2017-एमओपीटी.—** महापत्तन प्रशुल्क न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महा पत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, मोरमुगाव पत्तन न्यास पर बर्थ संख्या 5क और 6क पर इसके प्रचालन कार्यों के लिए साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) के दर मानों के संशोधन के संबंध में इस प्राधिकरण द्वारा पारित प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/40/2016-एसडब्ल्यूपीएल दिनांक 17 नवम्बर 2016 के संबंध में मोरमुगाव पत्तन न्यास (एमओपीटी) द्वारा प्रस्तुत समीक्षा आवेदन का निपटान करता है, जैसाकि इसके साथ संलग्न आदेश में दिया गया है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

**संख्या टीएएमपी/14/2017-एमओपीटी**

मोरमुगाव पत्तन न्यास

---

आवेदक

**कोरम:**

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमण्यन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

**आदेश**

(सितम्बर 2017 के इस 15वें दिन को पारित)

यह मामला मोरमुगाव पत्तन न्यास पर बर्थ संख्या 5क और 6क पर इसके प्रचालन कार्यों के लिए साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) के दर मानों के संशोधन के संबंध में इस प्राधिकरण द्वारा पारित प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/40/2016-एसडब्ल्यूपीएल दिनांक 17 नवम्बर 2016 के संबंध में मोरमुगाव पत्तन न्यास (एमओपीटी) द्वारा इसके पत्र दिनांक 10 फरवरी 2017 के साथ गोपनीय रूप से प्रस्तुत समीक्षा आवेदन से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण ने अपने आदेश संख्या टीएमपी/40/2016-एसडब्ल्यूपीएल दिनांक 17 नवम्बर 2016 द्वारा एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर और 2005 के दिशा निर्देशों के अनुपालन में साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) की दर मानों को संशोधित किया था। 17 नवम्बर 2016 को अनुमोदित किए गए दर मानों को गजट संख्या 433 द्वारा 30 नवम्बर 2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। भारत के राजपत्र में दर मानों को अधिसूचित करने से संबंधित आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन समाप्त होने के पश्चात से संशोधित दर मान प्रवृत्त हुए थे। दर मानों की वैधता की तारीख 31 मार्च, 2019 निर्धारित की गई है। इस प्राधिकरण द्वारा पारित आख्यापित आदेश गजट संख्या 10 द्वारा 6 जनवरी 2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

2.2. उपर्युक्त आदेश में, इस प्राधिकरण ने 17 नवम्बर 2016 के आदेश के पैरा 13 (xxx) विनिर्दिष्ट लागत विवरण और विश्लेषण द्वारा प्रतिबिंबित लागत स्थिति के आधार पर तुलनात्मक गतिविधियों के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा 34% और 17% की प्रशुल्क वृद्धि के अनुरोध की तुलना में कार्गो प्रहस्तन प्रभार में 27.80% और बर्थ किराया प्रभार में 10% प्रशुल्क वृद्धि का अनुमोदन प्रदान किया गया था।

2.3. प्रशुल्क आदेश के संगत उद्धरण सुलभ संदर्भ के लिए पुनः उद्धृत किए गए हैं:

“वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए समेकित लागत विवरण और प्रमुख गतिविधि वार लागत विवरणों को उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार संशोधित किया गया है। संशोधित लागत विवरण अनुबंध – II (क) से (ग) के रूप में संलग्न हैं। वित्तीय/लागत विवरणों से प्रकट परिणामों के संबंध में संक्षिप्त स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:

विवरण	प्रचालन आव ( ' लाख में )				निवल आधिस्य (+) /पाटा (-) विगत आधिस्य के समायोजन के पश्चात ( ' लाख में )				निवल आधिस्य (+) /पाटा (-) प्रचालन आव की % के रूप में			औसत आधिस्य/पाटा %
	2016-17	2017-18	2018-19	Total	2016-17	2017-18	2018-19	Total	2016-17	2017-18	2018-19	
संपूर्ण टर्मिनल के लिए समेकित लागत विवरण	16428.31	16413.03	16401.59	49242.93	(1612.79)	(2675.68)	(3425.78)	(7714.25)	(9.82%)	(16.30%)	(20.89%)	(15.7%)
कार्गो प्रहस्तन गतिविधि	10046.00	10046.00	10046.00	30138.00	(4076.82)	(5179.12)	(5999.06)	(15255.00)	(40.58%)	(51.55%)	(59.72%)	(50.62%)
बर्थ किराया गतिविधि	6382.31	6367.03	6355.59	19104.93	2464.03	2503.45	2573.27	7540.75	38.61%	39.32%	40.49%	39.47%

एसडब्ल्यूपीएल ने संशोधित प्रस्ताव में भण्डारण प्रभागों को छोड़कर कार्गो प्रहस्तन प्रभागों में 34% की वृद्धि और बर्थ किराया प्रभागों में 17% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है।

एसडब्ल्यूपीएल के दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करते समय, एमओपीटी ने यह उल्लेख किया है कि अदानी टर्मिनल पर कार्गो प्रहस्तन प्रभार ₹247.20 प्रति टन है और बर्थ संख्या 8 के लिए निर्धारित अग्रिम प्रशुल्क ₹248.10 प्रति टन है। तुलनात्मक दृष्टि से एसडब्ल्यूपीएल टर्मिनल की विद्यमान दर ₹130.70 है और इसके बाद प्रस्तावित वृद्धि ₹169.91 होगी, जोकि अदानी टर्मिनल और इसके साथ-साथ बर्थ संख्या 8 और 9 के प्रभागों की तुलना में लगभग 30% कम है। एमओपीटी ने यह भी उल्लेख किया है कि एसडब्ल्यूपीएल बर्थ के प्रस्तावित बर्थ किराया प्रभार अदानी टर्मिनल के बर्थ किराया प्रभागों और बर्थ संख्या 8 और 9 के प्रभागों से काफी अधिक है। विदेशगामी पोत के लिए अदानी टर्मिनल और बर्थ संख्या 8 और 9 के बर्थ किराया प्रभार क्रमशः ₹0.66 और ₹0.84 प्रति जीआरटी प्रति घंटा है जबकि एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तावित ₹2.55 प्रति जीआरटी प्रति घंटा है। इस संबंध में, यह उल्लेख करना उपयुक्त प्रतीत होता है कि 2008 के अग्रिम प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विनियमित पीपीपी प्रचालकों के लिए निर्धारित प्रशुल्क का एमओपीटी द्वारा एसडब्ल्यूपीएल से की गई तुलना उपयुक्त नहीं है, जिसके प्रशुल्क 2005 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं क्योंकि वे अलग प्रकार के दिशा-निर्देशों के द्वारा विनियमित होते हैं।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि विद्यमान दरों पर 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए 15.7% की निवल समग्र कमी समग्र लागत स्थिति पर प्रतिबिंबित होती है। सही मायनों में, इन तीन वर्षों की अवधि के लिए समग्र निवल घाटा ₹7714.25 लाख है। यह देखने में आया है कि कार्गो प्रहस्तन गतिविधि में कुल घाटा इन तीन वर्षों की अवधि के लिए ₹15255 लाख है, जोकि बर्थ किराया गतिविधि में ₹7540.75 लाख के निवल समग्र आधिक्य द्वारा क्रास रूप से सब्सिडाइज्ड किया जा रहा है और संपूर्ण टर्मिनल के लिए शेष निवल घाटा ₹7714.25 लाख है। इससे वर्तमान प्रशुल्क चक्र में ₹7714.25 लाख के अनुमानित निवल घाटे को पूरा करने के लिए एसडब्ल्यूपीएल के विद्यमान प्रशुल्क में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। तब तक, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश प्रवृत्त हो गया है। यह जनवरी, 2016 के प्रारंभ से हो सकता है। इसलिए, प्रशुल्क वृद्धि की इस प्रकार अनुमति दी जाती है ताकि 2016-17 से 2018-19 के इन तीन वर्ष के प्रशुल्क चक्र के शेष 27 महीनों में ₹7714.25 लाख का घाटा पूरा हो सके। इस प्रयोजन के लिए, यदि हम गतिविधि लागत स्थिति को देखें, तो प्रशुल्क में 39.47% की अत्यधिक कमी करने के लिए बर्थ किराया बढ़ाना होगा। जबकि कार्गो प्रहस्तन गतिविधि 50.62% की अत्यधिक वृद्धि होगी। कार्गो प्रहस्तन गतिविधि में अत्यधिक वृद्धि की अनुमति देने के बजाए और बर्थ किराया गतिविधि में अत्यधिक कमी को प्रभावित करने की बजाए, यदि एक्रास द बोर्ड वृद्धि की अनुमति दी जाती है तो यह 20.89% बनती है। तथापि एसडब्ल्यूपीएल ने बर्थ किराया में 17% की वृद्धि करने और कार्गो प्रहस्तन गतिविधि में 34% वृद्धि करने का अनुरोध किया है। जैसाकि पहले ऊपर कहा गया है, एमओपीटी ने यह चिंता प्रकट की है कि एसडब्ल्यूपीएल पर बर्थ किराया प्रभार काफी अधिक है और यह भी कि यह पतन बर्थ किराया प्रभारों से कोई राजस्व अंश अर्जित नहीं करता है। अतः एसडब्ल्यूपीएल द्वारा जिस स्तर से अधिक बर्थ किराया में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है, उसकी अनुमति देना विवेकपूर्ण नहीं है। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए और बर्थ किराया में वृद्धि के अनुरोध के बारे में एमओपीटी द्वारा व्यक्त की गई चिंता को ध्यान में रखते हुए यह प्राधिकरण एसडब्ल्यूपीएल द्वारा किए गए 17% की वृद्धि के अनुरोध की तुलना में बर्थ किराया में 10% की प्रशुल्क वृद्धि की मंजूरी प्रदान करता है। इस संबंध में जनवरी 2017 से 31 मार्च, 2019 तक अतिरिक्त राजस्व ₹1431.82 लाख होने का अनुमान है। ₹6282.43 लाख का शेष घाटे की पूर्ति कार्गो प्रहस्तन प्रभार (भण्डारण प्रभार को छोड़कर) में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा 34% की वृद्धि (भण्डारण प्रभार को छोड़कर) के अनुरोध की तुलना में 27.80% की वृद्धि की अनुमति प्रदान करके की जाती है। एसडब्ल्यूपीएल ने भण्डारण प्रभार के संबंध में विद्यमान स्थिति को बनाए रखने का प्रस्ताव किया और इसका अनुमोदन किया जाता है।

इस प्राधिकरण द्वारा ₹7714.25 लाख के घाटे को पूरा करने के लिए अनुमोदित विद्यमान प्रशुल्क में वृद्धि को दर्शाने से संबंधित गणना नीचे दी गई :

(₹ लाख में)

विवरण			योग
गत अवधि के आधिक्य के समायोजन के पश्चात संपूर्ण टर्मिनल के लिए वर्तमान प्रशुल्क चक्र के लिए कुल घाटा			7,714.25
	कार्गो से संबंधित	पोत से संबंधित	
जनवरी 2017 से मार्च 2017 तक 3 महीनों के लिए यथानुपात राजस्व	2,511.50	1,595.58	4,107.08
वर्ष 18 – 2017 से 19-2018 तक के वर्षों के लिए अनुमानित राजस्व	20,092.00	12,722.62	32,814.62
जनवरी 2017 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए कुल राजस्व	22,603.50	14,318.20	36,921.70
बर्थ किराया में मंजूर की गई 10% प्रशुल्क वृद्धि से अनुमानित अतिरिक्त राजस्व	-	1,431.82	-

कार्गो प्रहस्तन प्रभार में वृद्धि करके पूरा किया गया शेष घाटा [₹7,714.25 – 1,431.82]	6,282.43	-	-
कार्गो प्रहस्तन प्रभार में मंजूर की गई प्रतिशत वृद्धि (जिसमें भण्डारण प्रभार सम्मिलित नहीं है) (एसडब्ल्यूपीएल प्रस्तावित 34%)	27.79% ( 27.80% के पूर्णांक में )	-	-

2.4 17 नवम्बर 2016 के उक्त आदेश के संदर्भ में, लाइसेंसधारी पत्तन, मोरमुगाव पत्तन न्यास (एमओपीटी) ने 10 फरवरी 2017 को समीक्षा आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा एसडब्ल्यूपीएल के दर मानों को संशोधित करते हुए इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17 नवम्बर 2016 के पारित किए गए आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।

2.5 एमओपीटी द्वारा अपने समीक्षा आवेदन में उठाए गए प्रमुख मुद्दे संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:

- (i) एसडब्ल्यूपीएल ने कार्गो प्रहस्तन प्रभारों (सीआरसी) में 34% की वृद्धि और बर्थ किराया प्रभारों में 17% की वृद्धि का अनुरोध किया था। टीएएमपी द्वारा पारित आदेश के साथ संलग्न अनुबंध से यह देखा गया है कि कार्गो प्रहस्तन गतिविधि से 50.02% का घाटा हुआ है और बर्थिंग गतिविधि में 39.47% का आधिक्य हुआ है। हालांकि बर्थिंग गतिविधि में आधिक्य हुआ है, बर्थ किराया प्रभारों में 10% की वृद्धि की गई थी और कार्गो प्रहस्तन प्रभारों में केवल 30% की वृद्धि की गई थी जबकि कार्गो प्रहस्तन गतिविधि 50.02% तक का घाटा हुआ है।
- (ii) हस्ताक्षरित लाइसेंस करार के अनुसार, एसडब्ल्यूपीएल को केवल कार्गो प्रहस्तन प्रभारों पर रायल्टी का भुगतान करना है न कि बर्थ किराया प्रभारों पर। इसलिए, क्रास सब्सिडाइजेशन और समग्र आधिक्य के बहाने पत्तन को राजस्व का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बर्थ किराया प्रभारों में वृद्धि में परिणामस्वरूप एसडब्ल्यूपीएल को अनुचित रूप से संपन्नता की स्थिति बनेगी और पत्तन को वित्तीय नुकसान होगा। पत्तन ने इस मुद्दे को हमारे ऊपर संदर्भित पत्र द्वारा उठाया है। तथापि, एसडब्ल्यूपीएल ने बर्थ किराया दरों में वृद्धि को उचित ठहराते हुए कोई ठोस उत्तर नहीं दिया है।
- (iii) यह भी कि एसडब्ल्यूपीएल की कार्गो प्रहस्तन दरें बहुत ही कम हैं और बर्थ संख्या 7,8 और 9 के समीपवर्ती पीपीपी प्रचालकों की 45% की सीमा तक की दरों की तुलना में बर्थ किराया बहुत अधिक है।

3. इस प्रकार, एमओपीटी ने इस प्राधिकरण से 17 नवम्बर, 2016 के आदेश की समीक्षा करने और पत्तन के हित में कार्गो प्रहस्तन गतिविधियों के प्रभारों में वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

4.1 मार्च, 2005 के प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के खण्ड 3.3.1 में यह विनिर्दिष्ट है कि किसी भी प्रशुल्क आदेश की समीक्षा से संबंधित आवेदन पर सम्बद्ध प्रक्रियाओं में सुविचारित रिकार्डों को देखते हुए स्पष्ट त्रुटियों की सीमाओं में ही विचार किया जाएगा, बशर्ते, ऐसा आवेदन भारत के राजपत्र में आदेश के अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाए। संदर्भित विस्तृत आख्यापित आदेश 6 जनवरी, 2017 को अधिसूचित हुआ था और एमओपीटी ने 10 फरवरी, 2017 को समीक्षा आवेदन प्रस्तुत किया है, जो 30 दिनों की निर्धारित सीमा के भीतर है।

4.2 विगत में, ऐसे उदाहरण रहे हैं, जिनमें कुछेक निजी टार्मिनल प्रचालकों ने अपने प्रशुल्क आदेशों की समीक्षा के लिए आवेदन दिए हैं। प्रस्तावित वीओटी टार्मिनल प्रचालकों द्वारा प्रस्तुत ऐसे समीक्षा प्रस्तावों पर विचार किया गया था और प्रचलित परामर्श प्रक्रिया का पालन करते हुए इस प्राधिकरण द्वारा उनका निपटान किया गया था। तथापि, वर्तमान मामले में, लाइसेंसधारी पत्तन (एमओपीटी) ने एसडब्ल्यूपीएल के दर मानों को संशोधित करते हुए इस प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 17 नवम्बर, 2016 के आदेश पर समीक्षा आवेदन प्रस्तुत किया है। चूंकि, एमओपीटी एक लाइसेंसधारी पत्तन है, और एमओपीटी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करते हुए, जैसाकि उपर्युक्त पैरा 2.2 में दिए गए हैं, एमओपीटी के समीक्षा आवेदन पर अलग प्रशुल्क मामले के रूप में कार्रवाई की गई है।

5.1 परामर्श की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, एमओपीटी के पत्र दिनांक 10 फरवरी, 2017 की प्रति हमारे पत्र दिनांक 15 फरवरी, 2017 द्वारा उनसे अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध करते हुए साउथ वेस्ट पत्तन लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) को और

संबंधित उपभोक्ताओं/उपभोक्ता संगठनों को अग्रेषित की गई थी। संबंधित उपभोक्ताओं/उपभोक्ता संगठनों से हमें कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

5.2 एसडब्ल्यूपीएल ने अपने ई-मेल दिनांक 9 मार्च, 2017 द्वारा एमओपीटी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपनी टिप्पणीयां अग्रेषित की हैं।

6. इस मामले में एमओपीटी परिसर में 30 मार्च, 2017 को संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया था। संयुक्त सुनवाई में, एमओपीटी और एसडब्ल्यूपीएल ने अपने-अपने निवेदन किए हैं।

7.1. संयुक्त सुनवाई में, यह बात ध्यान में लायी गई थी कि एसडब्ल्यूपीएल के दरमानों में इस प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई प्रशुल्क वृद्धि के लिए कारणों को आदेश में विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है। संयुक्त सुनवाई में, एमओपीटी ने यह उल्लेख किया है कि पत्तन ने कार्गो प्रहस्तन प्रभार में अधिक प्रशुल्क वृद्धि और बर्थ किराया प्रभार में अपेक्षाकृत कम प्रशुल्क वृद्धि की इच्छा व्यक्त की। इस संदर्भ में, एसडब्ल्यूपीएल ने यह उल्लेख किया कि यदि कार्गो प्रहस्तन प्रभार में अधिक वृद्धि की जाती है तो यातायात अन्य पत्तनों की ओर रुख करेगा। एमओपीटी ने संयुक्त सुनवाई में उल्लेख किया कि पत्तन यह नहीं चाहता कि कार्गो प्रहस्तन प्रभारों में उसके द्वारा की गई अधिक प्रशुल्क वृद्धि के कारण परिवहन में कमी हो।

एमओपीटी और एसडब्ल्यूपीएल द्वारा व्यक्त की गई स्थिति का समाधान करने की दृष्टि से, दोनों ने एक साथ मिलकर बातचीत करने के लिए और एमओपीटी द्वारा प्रस्तुत समीक्षा आवेदन पर सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए सहमति व्यक्त की ताकि नवम्बर, 2016 के प्रशुल्क आदेश में मूल्यांकित 2016-17 से 2019-20 तक के वर्षों के लिए ₹77.14 करोड़ के समग्र घाटे को पूरा किया जा सके।

7.2 तदनुसार, संयुक्त सुनवाई में बनी सहमति के अनुसार, एमओपीटी और एसडब्ल्यूपीएल से हमारे पत्र दिनांक 5 जून, 2007 को अनुरोध किया गया था कि वे एक साथ मिलकर विचार करें और एमओपीटी द्वारा प्रस्तुत समीक्षा आवेदन पर एक सप्ताह के भीतर इस प्रकार से सौहार्दपूर्ण समाधान का पता लगाएं कि पारस्परिक रूप से होने वाली सहमति से वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के लिए ₹77.14 करोड़ के समग्र घाटे को पूरा किया जा सके। इसके पश्चात, इस दिशा में आगे कार्रवाई करने के लिए शीघ्र उत्तर देने के लिए हमारे 20 जून, 2017 के पत्र द्वारा एमओपीटी और एसडब्ल्यूपीएल को एक अनुस्मारक भी भेजा गया था।

7.3 एमओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 2 अगस्त, 2017 को उत्तर देते हुए, इस बात उल्लेख करते हुए कि आदेश की समीक्षा के परिणामस्वरूप कार्गो प्रहस्तन प्रभारों में कमी आ सकती है, जिससे पत्तन की अर्जित आय में राजस्व अंश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह कहा कि कार्गो प्रहस्तन गतिविधियों के लिए प्रभारों की समीक्षा के लिए पत्तन द्वारा प्रस्तुत समीक्षा आवेदन को वापिस लेने के लिए प्रस्ताव किया है।

8. इस मामले में, परामर्श से संबंधित प्रक्रियाओं के संबंध में इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड उपलब्ध है। पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियां और उस वाद-विवाद के उद्घरण संबंधित पक्षकारों को अलग से भेजे जाएंगे। ये विवरण हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

9.1 जैसाकि पहले ही ध्यान में लाया गया है, यह प्राधिकरण आदेश सं. टीएएमपी/40/2016-एसडब्ल्यूपीएल दिनांक 17 नवम्बर, 2016 में कार्गो प्रहस्तन प्रभार में तुलनात्मक गतिविधि के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा 34% और 17% की प्रशुल्क वृद्धि के अनुरोध की तुलना में 27.80% और बर्थ किराए प्रभार में 10% की प्रशुल्क वृद्धि प्रदान कर दी है। विस्तृत आदेश के पैरा 13 (xxv) में उक्त आदेश में प्रदान की गई अनुमति प्रशुल्क वृद्धि के विस्तार से संबंधित है।

9.2 एमओपीटी ने समीक्षा आवेदन में यह उल्लेख किया है कि बर्थ किराया में टीएएमपी द्वारा मंजूर की गई प्रशुल्क वृद्धि के परिणामस्वरूप अनुचित समृद्धि होगी। इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि इस प्राधिकरण द्वारा पारित नवम्बर, 2016 के आख्यापित आदेश लागत विवरण में दर्शाए गए वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के वर्षों के लिए ₹77.14 करोड़ के निवल घाटे को पूरा करने के लिए है। उक्त आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा जिस प्रशुल्क की वृद्धि की अनुमति प्रदान की गई है, वह ₹77.14 करोड़ के उक्त घाटे को पूरा करने के लिए है। इसलिए, एसडब्ल्यूपीएल को उक्त आदेश में प्रशुल्क वृद्धि की अनुमति के कारण कोई अनुचित समृद्धि नहीं है।

9.3 नीति निर्देश के रूप में एमपीटी अधिनियम 1963 की धारा 111 के अंतर्गत इस प्राधिकरण को सरकार द्वारा जारी प्रशुल्क निर्देश 2005 द्वारा यह प्राधिकरण निर्देशित है। यह प्राधिकरण वीओटी प्रचालकों, जिसमें एसडब्ल्यूपीएल सम्मिलित है, के प्रशुल्कों का निर्धारित करने से संबंधित प्रशुल्क दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। वीओटी प्रचालक द्वारा लाइसेंसधारी पत्तन को राजस्व अंश का भुगतान देय होने अथवा देय न होने के अनुसार प्रशुल्क का समायोजन करने के लिए प्रशुल्क निर्देशों में कोई प्रावधान नहीं है।

बीओटी टर्मिनलों के सभी मामलों में इस प्राधिकरण तथा 2005 के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रशुल्क निर्धारित की पद्धति का समान रूप से पालन किया जाता है।

10. किसी भी मामले में, एमओपीटी ने स्वयं नवम्बर, 2016 में इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की समीक्षा के लिए पत्तन द्वारा प्रस्तुत समीक्षा आवेदन को वापिस लेने के लिए प्रस्तुत किया है।

11. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त दर्शाए गए कारणों से, तथा सामूहिक रूप से विवेकपूर्ण विचार करने के आधार पर यह प्राधिकरण एमओपीटी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 10 फरवरी 2017 के पत्तन द्वारा वापिस लिए गए समीक्षा आवेदन के रूप में निपटान करता है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[ विज्ञापन III/4/असा./291/17 ]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 25th October, 2017

**No.TAMP/14/2017- MOPT.**— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the review application filed by the Mormugao Port Trust (MOPT) on the tariff Order No.TAMP/40/2016-SWPL dated 17 November 2016 passed by this Authority in respect of revision of the Scale of Rates of South West Port Limited (SWPL) for its operations at the berth nos.5A and 6A at the Mormugao Port Trust, as in the Order appended hereto.

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### No. TAMP/14/2017–MOPT

Mormugao Port Trust

- - -

Applicant

### QUORUM:

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

### ORDER

(Passed on this 15th day of September 2017)

This case relates to the review application filed by the Mormugao Port Trust (MOPT) under cover of its letter dated 10 February 2017 on the tariff Order No.TAMP/40/2016-SWPL dated 17 November 2016 passed by this Authority in respect of revision of the Scale of Rates of South West Port Limited (SWPL) for its operations at the berth nos.5A and 6A at the Mormugao Port Trust.

2.1. This Authority vide its Order no.TAMP/40/2016-SWPL dated 17 November 2016 had revised the Scale of Rates of the South West Port Limited (SWPL) based on the proposal filed by SWPL and following 2005 Tariff Guidelines. The SOR approved on 17 November 2016 was notified in the Gazette of India on 30 November 2016 vide Gazette No.433. The revised SOR came into force after expiry of 30 days from the date of notification of the Order notifying the SOR in the Gazette of India. The validity of the SOR is prescribed till 31 March 2019. The speaking Order passed by this Authority was notified in the Gazette of India on 6 January 2017 vide Gazette No.10.

2.2. In the said Order, this Authority had granted tariff increase of 27.80% in cargo handling charge and 10% in berth hire charge as against tariff increase of 34% and 17% sought by SWPL for the corresponding activities based on the cost position reflected by the cost statement and analysis contained in para 13(xxv) of the Order dated 17 November 2016.

2.3. The relevant extract of the tariff Order is reproduced below for ease of reference:

*“The consolidated cost statement and main activity-wise cost statements for the years 2016-17 to 2018-19 have been modified in line with the above analysis. The modified cost statements are attached as Annex – II (a) to (c). The summarised position of the results disclosed by the financial / cost statements is tabulated below:*

Particulars	Operating Income (₹ in lakhs)				Net Surplus (+) / Deficit (-) after adjustment of past surplus (₹ in lakhs)				Net Surplus (+) / Deficit (-) as a % of operating Income			Avg. surplus/ deficit %
	2016-17	2017-18	2018-19	Total	2016-17	2017-18	2018-19	Total	2016-17	2017-18	2018-19	
Consolidated cost statement for the terminal as a whole	16428.31	16413.03	16401.59	49242.93	(1612.79)	(2675.68)	(3425.78)	(7714.25)	(9.82%)	(16.30%)	(20.89%)	(15.7%)
Cargo handling Activity	10046.00	10046.00	10046.00	30138.00	(4076.82)	(5179.12)	(5999.06)	(15255.00)	(40.58%)	(51.55%)	(59.72%)	(50.62%)
Berth hire activity	6382.31	6367.03	6355.59	19104.93	2464.03	2503.45	2573.27	7540.75	38.61%	39.32%	40.49%	39.47%

The SWPL in the revised proposal, has proposed 34% increase in the cargo handling charges except storage charges and 17% increase in the berth hire charges.

While furnishing its comments on the proposal for general revision of Scale of Rates of SWPL, the MOPT has stated that the cargo handling charges at Adani Terminal is ₹ 247.20 per tonne and upfront tariff fixed for Berth No. 8 is ₹ 248.10 per tonne. In comparison, the existing rate of SWPL terminal is ₹ 130.70 and even after the proposed increase would ₹ 169.91 which is about 30% lesser than the charges of Adani Terminal as well as Berth No.8 and 9. The MOPT has also stated that the proposed berth hire charges of SWPL berth are substantially higher than berth hire charges of Adani Terminal and Berth No.8 and 9 charges. The Berth Hire charges of Adani Terminal and Berth No.8 and 9 are ₹ 0.66 and ₹ 0.84 per GRT per hour respectively for foreign going vessel as compared to ₹ 2.55 per GRT per hour proposed by SWPL. In this connection, it is relevant to mention that the comparison drawn by the MOPT of tariff fixed for the PPP operators governed under upfront tariff guidelines of 2008 with SWPL whose tariff is fixed under 2005 Guidelines is not relevant as they are governed by different set of guidelines.

It is evident from the above table, that the overall cost position reflects an overall net deficit of 15.7% for the period 2016-17 to 2018-19 at the prevailing rates. In absolute terms, the overall net deficit is ₹ 7714.25 lakhs for the three years period.

It is seen that the aggregate deficit in the cargo handling activity is ₹ 15255 lakhs for the three years period which is being cross subsidized by overall net surplus of ₹ 7540.75 lakhs in the berth hire activity and the remaining net deficit for the terminal as a whole is ₹ 7714.25 lakhs. This warrants increase in the existing tariff of the SWPL to cover the estimated net deficit of ₹ 7714.25 lakhs in the current tariff cycle. By the time the Order approved by this Authority comes into effect it may be beginning of January 2016. Therefore, tariff increase is granted in such a way to cover the deficit of ₹ 7714.25 lakhs in the remaining 27 months of the three year tariff cycle of 2016-17 to 2018-19.

For this purpose, if we go by the activity wise cost position, then the berth hire will call for a steep reduction of 39.47% in the tariff whereas, the cargo handling activity will call for a steep increase of 50.62%. Instead of granting steep increase in cargo handling activity and effecting steep decrease in the berth hire activity if across the board increase is to be accorded it comes to 20.89%. However, SWPL has sought 17% increase in berth hire and 34% increase in cargo handling expense. As stated earlier, the MOPT has raised concern that the berth hire charges at SWPL is on a higher side and also the port does not earn any revenue share on berth hire charges. Hence, it is not prudent to grant an increase in berth hire more than the level sought by the SWPL. In view of the above position and in view of the concern raised by the MOPT about increase sought in the berth hire, this Authority decides to grant tariff increase of 10% in the berth hire as against 17% increase sought by the SWPL. The additional revenue on this account is estimated to be ₹ 1431.82 lakhs from January 2017 till 31 March 2019. The balance deficit of ₹ 6282.43 lakhs is bridged by granting 27.80% increase in cargo handling charge (except storage charge) as against 34% increase sought by the SWPL (except storage charge). The SWPL has proposed status quo in storage charge and the same is approved.

A calculation showing increase in the existing tariff granted by this Authority to meet the deficit of ₹7714.25 lakhs is given below:

			(₹ in Lakhs)
<i>Particulars</i>			<i>Total</i>
<b>Total Deficit for the current tariff cycle for the terminal as a whole after adjustment of past period surplus</b>			<b>7,714.25</b>
	<i>Cargo related</i>	<i>Vessel related</i>	
<i>Prorated revenue for 3 months i.e., January 2017 to March 2017</i>	2,511.50	1,595.58	4,107.08
<i>Estimated Revenue for the years 2017-18 to 2018-19</i>	20,092.00	12,722.62	32,814.62
<b>Total Revenue for a period from January 2017 to March 2019</b>	22,603.50	14,318.20	36,921.70
<b>Estimated Additional revenue from 10% Tariff increase granted in berth hire.</b>	-	<b>1,431.82</b>	-
<b>Balance deficit bridged by increasing cargo handling charge. [₹7,714.25 – 1,431.82]</b>	<b>6,282.43</b>	-	-
<i>% increase granted in cargo handling charge (excluding storage charges) (SWPL proposed 34%)</i>	27.79% (Rounded to 27.80%)	-	-

2.4. With reference to the said Order dated 17 November 2016, the Licensor Port, Mormugao Port Trust (MOPT) has filed a Review Application on 10 February 2017 seeking review of the Order dated 17 November 2016 passed by this Authority revising the SOR of SWPL.

2.5. The main points made by the MOPT in its review application are summarised below:

- (i). SWPL had sought an increase of 34% in Cargo Handling Charges (CRC) and 17% in berth hire charges. From the Annexure to the Order passed by TAMP it is observed that, the Cargo handling activity is deficit to the extent of 50.02% and berthing activity is in surplus by 39.47%. Though the berthing activity is in surplus, berth hire charges were increased by 10% and cargo handling charges were increased only by 30% although, Cargo handling activity is in deficit by 50.02%.
- (ii). As per the License agreement signed, SWPL has to pay royalty only on Cargo Handling Charges and not on berth hire charges. Therefore, there should not be any loss of revenue to the Port in the guise of cross subsidization and overall surplus. The increase in berth hire charges will result in unjust enrichment to SWPL and financial loss to the Port. The Port has raised this point vide our above referred letter. However, SWPL has not given a convincing reply justifying the increase in berth hire rates.
- (iii). Also, the SWPL Cargo handling rates are very much less and berth hire is higher as compared to those of the neighbouring PPP operators of Berth No.7, 8 & 9 to the extent of 45%.

3. Thus, the MOPT has requested this Authority to review the Order dated 17 November 2016 and increase the charges for cargo handling activities in the interest of the Port.

4.1. Clause 3.3.1. of the tariff guidelines of March 2005 stipulates that application of review of any tariff Order will be entertained to the limited extent of errors apparent on the face of records considered in the relevant proceedings, provided such an application is filed within 30 days of the notification of the Order in the Gazette of India. The detailed speaking tariff Order in reference was notified on 6 January 2017 and the MOPT has filed the review application on 10 February 2017, which is within the prescribed time limit of 30 days.

4.2. In the past, there have been instances where a few private terminal operators have made an application for review of their tariff Orders. Such review proposals filed by the proposed BOT terminal operators were entertained and have been disposed by this Authority following the usual consultation process. However, in the present case, the



licensor Port (MOPT) has filed a review application on the Order dated 17 November 2016 passed by this Authority revising the SOR of SWPL. Since, the MOPT is a licensor port and considering the points made by the MOPT as brought out at para 2.2 above, the review application of MOPT is taken up as a separate tariff case.

5.1. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of MOPT letter dated 10 February 2017 was forwarded to South West Port Limited (SWPL) and concerned users/ user organisations seeking their comments vide our letter dated 15 February 2017. We have not received comments from concerned users/ user organisations.

5.2. The SWPL has vide its email dated 9 March 2017 forwarded its comments on the points made by MOPT.

6. A joint hearing in this case was held on 30 May 2017 at the MOPT premises. At the joint hearing, the MOPT and SWPL have made their submissions.

7.1. At the joint hearing, it was brought out that the reasons for tariff increase granted by this Authority in the SOR of the SWPL is explained in detail in the Order. At the joint hearing, the MOPT has stated that port wants higher tariff increase in cargo handling charge and lower tariff increase in the berth hire charge. In this context, the SWPL has pointed out that if cargo handling charge is increased further, then the traffic will get diverted to other ports. The MOPT at the joint hearing stated that port does not want the traffic to reduce on account of higher tariff increase sought by it in cargo handling charges.

In order to reconcile the position taken by MOPT and SWPL, both agreed to sit together and come up with an amicable solution on the review application filed by the MOPT so as to meet the overall deficit of ₹77.14 crores for the years 2016-17 to 2019-20 assessed in the tariff Order of November 2016.

7.2. Accordingly, as agreed at the joint hearing, MOPT and SWPL were requested vide our letter dated 5 June 2017 to sit together and come up with an amicable solution within a week's time on the review application filed by MOPT in such a way that mutually agreed position would enable the SWPL to bridge the overall deficit of ₹77.14 crores for the year 2016-17 to 2019-20. This was followed by a reminder to MOPT and SWPL vide our letter dated 20 June 2017 to expedite its response to enable us to proceed further.

7.3. In response, MOPT vide its letter dated 02 August 2017 citing that review of the Order may result in reduction in cargo handling charges which will adversely affect the revenue share earnings of the port, has proposed to withdraw the review application filed by the Port to review the charges for cargo handling activities.

8. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

9.1. As already brought out earlier, this Authority in the Order No.TAMP/40/2016-SWPL dated 17 November 2016 has granted tariff increase of 27.80% in cargo handling charge and 10% in berth hire charge as against tariff increase of 34% and 17% sought by SWPL for the corresponding activity. Para 13 (xxv) of the detailed Order elaborately deals with the tariff increase granted in the said Order.

9.2. The MOPT in the review application has made a statement that tariff increase granted by TAMP in berth hire will result in unjust enrichment. In this regard, it is to state that the November 2016 Speaking Order passed by this Authority is to bridge the net deficit at ₹77.14 crores for the years 2016-17 to 2018-19 reflected by the cost statement. Whatever tariff increase granted by this Authority in the said Order is to meet the said deficit of ₹77.14 crores. That being so, there is no unjust enrichment on account of tariff increase granted in the said Order to the SWPL.

9.3. This Authority is guided by the Tariff Guidelines of 2005 issued by the Government to this Authority under Section 111 of the MPT Act, 1963 as a policy direction. This Authority is bound to follow the tariff guidelines to determine the tariff of BOT operators, including SWPL. There is no provision in the Tariff Guidelines to adjust the tariff in accordance with the Revenue share payable or not payable by the BOT operator to the licensor port. The tariff determination methodology prescribed in the 2005 guidelines is uniformly followed by this Authority in all the cases of BOT Terminals.

10. In any case, the MOPT has itself proposed to withdraw the review application filed by the port to review the Order passed by this Authority in November 2016.

11. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority disposes of the review application dated 10 February 2017 filed by the MOPT as withdrawn by the port.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)  
[ADVT III/4/Exty./291/17]